



## परसपेक्टवि: भारत का हरति ऊर्जा परिवर्तन

### प्रलिमिंस के लयि:

[प्रधानमंतरी सुर्योदय योजना](#), संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP21), [पेरसि समझौता](#), [सतत् विकास लक्ष्य](#), [शुद्ध-शून्य उत्सर्जन](#), [राष्ट्रीय सतर पर नरिधारति योगदान](#), [रूफटॉप सोलर योजना](#), [फोटोवोल्टकि पैनल](#), [ऊर्जा परषिद](#), [पर्यावरण एवं जल, EV30@30](#), [PM-कुसुम](#), [UNFCCC COP26](#), [हरति हाइड्रोजन](#), [वैश्वकि जैव ईंधन गठबंधन \(GBA\)](#), [G20](#) ।

### मेन्स के लयि:

पेरसि समझौते के जनादेश को प्राप्ति करने में भारत के हरति ऊर्जा परिवर्तन का योगदान ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वृत्ति मंत्री ने अंतरमि बजट पेश कयि। यह भारत के नमिन कार्बन जलवायु लचीली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को गति देगा ।

- भारत का लक्ष्य [पेरसि समझौते](#) के तहत [राष्ट्रीय सतर पर नरिधारति योगदान](#) के अनुरूप अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करना है ।
- भारत के प्रधानमंतरी ने [प्रधानमंतरी सुर्योदय योजना](#) के माध्यम से घरों पर सौर पैनल स्थापति करने की योजना की घोषणा की ।

## नमिन कार्बन जलवायु लचीली अर्थव्यवस्था क्या है?

- [नमिन कार्बन जलवायु लचीली अर्थव्यवस्था](#) एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका लक्ष्य [ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन](#) को कम करना, [ग्लोबल वार्मिंग](#) और कोयला, तेल एवं गैस की खपत को सीमति करना है । इसे [हरति](#), [वृत्ताकार](#) या [सतत् अर्थव्यवस्था](#) के रूप में भी जाना जाता है । [नमिन कार्बन जलवायु लचीली अर्थव्यवस्था](#) की कुछ वशिषताएँ हैं:
  - यह [जीवाश्म ईंधन](#) के बजाय [सौर](#), पवन, पनबजिली और [जैव ईंधन](#) जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करती है, जैसे यह ऊर्जा खपत तथा अपशिष्ट को कम करने के लयि ऊर्जा दक्षता, संरक्षण एवं मांग प्रबंधन को बढ़ावा देती है ।
  - यह कार्बन सकि को बढ़ाने और वनों की कटाई तथा कमी से उत्सर्जन को कम करने के लयि नमिन कार्बन एवं जलवायु-स्मार्ट कृषि, वानिकी व भूमि उपयोग का समर्थन करती है ।
  - यह नमिन कार्बन और जलवायु-लचीली गतिविधियों तथा उत्पादों के लयि संसाधन एवं प्रोत्साहन जुटाने हेतु [हरति वृत्ति](#), [नविश व व्यापार](#) को प्रोत्साहति करती है ।
  - यह [सुनिश्चि करने के लयि कसंक्रमण के लाभ व लागत को उचित रूप](#) से साझा कर, जिससे सबसे कमजोर समूहों को संरक्षति एवं सशक्त बनाया जाता है, सामाजिक व पर्यावरणीय न्याय, समानता और समावेशन को बढ़ावा देती है ।

## पेरसि समझौता क्या है?

- **परचिय:**
  - जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लयि पेरसि में [संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन \(COP21\)](#) में वशि्व नेता **12 दसिबर, 2015** को एक ऐतिहासिक [समझौते](#) के लयि पेरसि पहुँचे ।
  - यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो **4 नवंबर, 2016** को लागू हुआ ।
  - **195** पार्टियों (194 राज्य और यूरोपीय संघ) [पेरसि समझौते](#) में शामिल हो गई हैं ।
  - यह [शुद्ध-शून्य उत्सर्जन](#) वाली वशि्व की ओर बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है ।
  - सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लयि समझौते का कार्यान्वयन भी आवश्यक है ।
- **लक्ष्य:**
  - वैश्विक तापमान वृद्धि को [पूर्व-औद्योगिक सतरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लयि वैश्विक GHG उत्सर्जन](#) को

पर्याप्त रूप से कम करना और इसे पूरव-औद्योगिकी स्तरों से **1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमिति करने के प्रयास** करना, यह मानते हुए कि इससे जलवायु परिवर्तन के जोखिमों तथा प्रभावों में काफी कमी आएगी।

- समय-समय पर इस समझौते के उद्देश्य और इसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करना।
- **जलवायु परिवर्तन** को कम करने, लचीलेपन को मजबूत करने और **जलवायु प्रभावों के अनुकूल क्षमताओं** को बढ़ाने के लिये विकासशील देशों को वित्तपोषण प्रदान करना।

#### कार्य:

- **पेरिस समझौता** देशों द्वारा की जाने वाली बढ़ती महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के पाँच वर्ष के चक्र पर काम करता है।
- प्रत्येक पाँच वर्ष में प्रत्येक देश से एक अद्यतन राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है जिसे **राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान (NDC)** के रूप में जाना जाता है।

## भारत का राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान क्या है?

- **UNFCCC** और उसके **पेरिस समझौते** के एक पक्ष के रूप में, भारत ने वर्ष 2015 में अपना पहला राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान (NDC) प्रस्तुत किया, जिसमें नमिनलखिति दो मात्रात्मक लक्ष्य शामिल थे:
  - वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने **सकल घरेलू उत्पाद** की उत्सर्जन तीव्रता को **33 से 35%** तक कम करना।
  - वर्ष 2030 तक **गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी वदियुत** स्थापति क्षमता प्राप्त करना।
- अगस्त 2022 में भारत ने अपने **NDC को अद्यतन** किया जिसके अनुसार इसका लक्ष्य:
  - उत्सर्जन को कम करने के लिये अपने **सकल घरेलू उत्पाद** की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 45% तक बढ़ाना है।
  - गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से संचयी वदियुत स्थापति क्षमता का **लक्ष्य वर्ष 2030 तक 50% तक बढ़ाना** है।
  - भारत ने **पेरिस समझौते** के तहत अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए वर्ष 2030 तक **500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता** प्राप्त करना है।

## प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है?

#### परचिय:

- भारतीय प्रधानमंत्री ने 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' शुरू की, जो एक नवाचार युक्त सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य देशभर के एक करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली या रूफटॉप सोलर पैनल स्थापति करना है।
- रूफटॉप सोलर एक **फोटोवोल्टिक प्रणाली** है जिसमें वदियुत उत्पादन करने वाले सौर पैनल आवासीय या व्यावसायिक भवन या संरचना की छत पर लगे होते हैं।

#### लाभ:

- यह **ग्रिड से जुड़ी वदियुत की खपत को कम** करता है और उपभोक्ता के लिये वदियुत लागत को बचाता है।
- रूफटॉप सोलर प्लांट से उत्पन्न अधशेष सौर ऊर्जा इकाइयों को मीटरिंग प्रवाधानों के अनुसार ग्रिड में नरियात किया जा सकता है।
- उपभोक्ता प्रचलति नयिमों के अनुसार अधशेष नरियातति वदियुत के लिये मौद्रिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

#### रूफटॉप सोलर प्रोग्राम:

- सरकार ने वर्ष 2014 में **रूफटॉप सोलर प्रोग्राम** लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक 40,000 मेगावाट (MW) या 40 गीगावाट (GW) की संचयी संस्थापति क्षमता हासिल करना था।
  - हालाँकि यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। जिसके परिणामस्वरूप, सरकार ने इसकी समय-सीमा वर्ष 2022 से बढ़ाकर वर्ष 2026 तक कर दी है।
- कुछ रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 40 गीगावॉट रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करने का एक बड़ा प्रयास है।

## भारत में वर्तमान सौर क्षमता क्या है?

- **कुल स्थापति क्षमता:** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दसिंबर 2023 तक भारत में छतों पर स्थापति **सोलर प्रणाली की क्षमता** लगभग 73.31 गीगावॉट तक पहुँच गई है। कुल सौर क्षमता के मामले में राजस्थान 18.7 गीगावॉट उत्पादन के साथ शीर्ष पर है। गुजरात 10.5 गीगावॉट के साथ दूसरे स्थान पर है।
- **छत पर सौर क्षमता:** दसिंबर 2023 तक कुल छत पर सौर **स्थापति क्षमता लगभग 11.08 गीगावॉट** है। छत पर स्थापति **सोलर प्रणाली क्षमता के संदर्भ में गुजरात 2.8 गीगावॉट** के साथ सूची में सबसे ऊपर है इसके बाद **महाराष्ट्र 1.7 गीगावॉट** के साथ दूसरे स्थान पर है।
  - **ऊर्जा, पर्यावरण और जल परषिद (CEEW)** की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कुल रूफटॉप सोलर प्रणाली के लगभग **20% की स्थापना** आवासीय क्षेत्र में की गई है तथा अधकिंश रूफटॉप सोलर प्रणालियाँ वाणज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में हैं।
    - रिपोर्ट के अनुसार, **भारत के लगभग 25 करोड़ घर छतों पर कुल 637 गीगावॉट की क्षमता की सोलर प्रणाली स्थापति** करने में सक्षम हैं तथा इसकी कुल क्षमता का मात्र एक-तहाई हिस्सा देश में संपूर्ण आवासीय क्षेत्रों की वदियुत की मांग को पूरा कर सकता है।

## जलवायु परिवर्तन की दशा में भारत की अन्य पहल क्या हैं?

- **EV को भारत का समर्थन:**

- भारत उन गनि-चुने देशों में शामिल है जो वैश्विक 'EV30@30 अभियान' का समर्थन करते हैं, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हस्सेदारी को न्यूनतम 30% तक करना है।
- ग्लासगो में आयोजित COP26 में जलवायु परिवर्तन शमन के लिये भारत द्वारा पाँच तत्त्वों (जिसें 'पंचामृत' कहा गया है) का समर्थन इसी दशा में जताई गई प्रतबिद्धता है।
- **नमिन-कार्बन संक्रमण में उद्योगों की भूमिका:**
  - भारत में सार्वजनिक और नजीक कषेत्र पहले से ही जलवायु चुनौतियों से नपिटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभा रहे हैं, जहाँ ग्राहकों एवं नविशकों में बढ़ती जागरूकता के साथ-साथ बढ़ती नयामक तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं से सहायता प्राप्त हो रही है।
- **राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मशिन:**
  - यह हरति हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहति करने और भारत को ईंधन का शुद्ध नरियातक बनाने हेतु एक कार्यक्रम है।
  - यह मशिन हरति हाइड्रोजन की मांग में वृद्धिलाने के साथ-साथ इसके उत्पादन, उपयोग और नरियात को बढ़ावा देगा।
- **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन:**
  - वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) को हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जैव ईंधन के वैश्विक उत्थान में तेजी लाने के लिये वैश्विक नेताओं द्वारा गठति कया गया है। यह गठबंधन अमेरिका, ब्राज़ील और भारत जैसे प्रमुख जैव ईंधन उत्पादक एवं उपभोक्ता देशों को एक साथ लाता है।
  - वैश्विक स्तर पर अभी तक 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन GBA में सम्मलति होने या इसका समर्थन करने के लिये सहमति जता चुके हैं। GBA हरति संवहनीय भवषिय के लिये वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है।
- **PM कुसुम:**
  - पीएम-कुसुम योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा ग्रामीण कषेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना तथा ग्रिड से जुड़े कषेत्रों में ग्रिड पर नरिभरता कम करने के लिये इसे वर्ष 2019 में शुरू कया गया था।
  - इसका उद्देश्य कसानों को उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापति करने और इसे ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है।
  - यह ग्रिड को अधशेष सौर ऊर्जा बेचने की अनुमति देकर कसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????:**

प्रश्न. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2015)

1. यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है।
2. यह एक गैर-बैंकगि वतितिय कंपनी है।

नीचे दयि गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

**??????:**

प्रश्न. "वहनीय (ऐफोरडेबल), वशिवसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये अनवार्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टपिपणी कीजयि। (2018)